हार का प्रवेश: बजट 2020

लेखक - प्रताप भानु मेहता (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

03 फरवरी, 2020

"बजट 2020 एक पंचवर्षीय योजना की तरह प्रतीत हो रहा है जिसके लक्ष्य कई हैं, लेकिन उसके लिए कोई रोड मैप नहीं है।"

बजट 2020 को एक ऐसे संदर्भ में प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी गंभीर स्थिति का सामना कर रही है, जहाँ स्पष्ट समाधान भी समस्याओं का निर्माण कर सकती है। यहाँ कमजोरी केवल एक या दो क्षेत्रों में नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को कई सारी समस्याओं ने जकड़ रखा है। इसलिए अब हमें एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति की आवश्यकता है।

हम जिस तनाव भरे स्थिति से गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए हमे एक विस्तारवादी नीति की भी आवश्यकता है लेकिन अब सवाल उठता है कि आप इसे कैसे अंजाम देंगे जहाँ वास्तविक राजकोषीय नीति (यदि राज्यों के घाटों को जोड़ा जाए) पहले से ही विस्तारवादी है? हमे ग्रामीण माँग में मंदी को संबोधित करने की आवशयकता है। लेकिन एक सवाल फिर उठता है कि आप इसे कैसे अंजाम देंगे, जब आपने मनरेगा और इससे जुड़ी प्रशासनिक मशीनरी को डेढ़ दशक से ठप कर दिया हो?

पूँजी निवेश बढ़ाने और अधिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की भी आवश्यकता है। देखा जाये तो पिछले 15 वर्षों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे का विस्तार, एक स्थायी वित्तीय योजना या मजबूत वित्तपोषण संस्थानों के बिना किया जा रहा है और यही इस संकट का कारण बना है। हालाँकि, इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है यदि हम महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे बिजली और अचल संपत्ति में वित्तपोषण को सही कर ले। बैंकिंग संकट अभी भी जारी है, जो यूपीए सरकार की पिछले छह वर्षों की धीमी कार्रवाई का नतीजा है।

स्वदेशी सोच और वैश्वीकरण के बीच तनाव कई चीजों में प्रकट होती है। उदाहरण के लिए इस बजट में उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत् कर प्रेषण होगा। हालाँकि, यहाँ पर हमारे पास सुसंगत कराधान नीति नहीं है, जिसकी हमें आवश्यकता है। इसके अलावा इससे भी बुरी बात यह है कि सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि वह सरलीकरण करना चाहती है या नियंत्रण करना। भारत की गिरती बचत दर भी एक प्रमुख चिंता का कारण है।

अब संस्थागत पक्ष पर नजर डालते हैं। सहकारी संघवाद का क्या होगा क्योंकि ऐसा लगता है कि वित्त आयोग फंड आवंटन के फार्मूले में बदलाव करके केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों को और अधिक नाजुक बनाने के पक्ष में है। निश्चित रूप से IBC एक अच्छी पहल थी, लेकिन कई सारी सरकारी पहलों की तरह ही यह सरकार के उदासीनता के कारण खतरे में है। पहली बार, भारत के डेटा की अखंडता गंभीर बना हुआ है। अल्पावधि-लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार एलआईसी जैसे सार्वजनिक संस्थानों के साथ छेड़-छाड़ कर रही है।

स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो बजट में अधिक खपत खर्च और पूँजीगत निवेश दोनों पर वित्त मंत्री की सावधानी एक सच्चाई की ओर इशारा करती है कि सरकार को अपने निष्पादन क्षमताओं पर कम विश्वास है। बजट में शिक्षा और रक्षा सरकार के निम्न श्रेणी में रहे, जबकि स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जिसका वित्तीय निहितार्थ स्पष्ट नहीं है। यह सब देख कर कोई भी बेहतर स्थिति के होने का अनुमान कैसे लगा सकता है। यह कैसे निश्चित हो सकता है कि अर्थव्यवस्था उस तरह से कार्य करे जैसा हम सोचते हैं।

हालाँकि, बजट में घोषित ऐसे कई विवरण हैं जो संभावित रूप से आशाजनक प्रतीत होते हैं। स्वच्छ पानी पर जोर एक अच्छी पहल है। बजट 2020 एक पंचवर्षीय योजना की तरह प्रतीत हो रहा है, जिसके लक्ष्य कई हैं, लेकिन उसके लिए कोई रोड मैप नहीं है। बजट में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए घोषित कॉर्पोरेट कर कटौती का कोई असर नहीं पड़ेगा।

यह बस एक सांत्वना देने के जैसा है। कॉर्पोरेट्स लाभांश पर कर नहीं चाहते हैं, इसलिए शायद सरकार ने यह कदम उठाया। लेकिन फिर सरकार ने बजट में कर सरलीकरण के नाम पर व्यक्तियों के लिए अनुपालन लागत को स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए कथित कर कटौती या सरलीकरण की बात कही, लेकिन इतने छोटे-छोटे स्लैब के निर्माण

के बाद शायद ही इसे सरलीकरण के रूप में देखा जाएगा। जैसे-जैसे बजट पर विश्लेषण आते जाएंगे, ये विरोधाभास स्पष्ट होते जाएंगे। बजट भाषण हमेशा कृषि के लिए समर्पित रहता है, लेकिन अंत में किसानों को बहुत कम ही मिलता है।

तो अब प्रश्न उठता है कि क्या बजट निराशाजनक है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इस बजट से कितनी उम्मीद लगा रखी थीं। आप शायद राहत की भावना महसूस कर सकते हैं कि सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, जिससे अर्थव्यवस्था और प्रभावित होती। आप वित्त मंत्री के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं। अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए जो चीजें होंगी, उसे बजट में शामिल नहीं किया जा सकता।

केंद्रीय बजट 2020

- **चर्चा में क्यों?**
- हाल ही में केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश किया।
- 21वीं सदी के तीसरे दशक के इस बजट में वित्त मंत्री ने दीर्घकालिक प्रभाव वाले कई सुधारों की घोषणा की। जिनका उद्देश्य लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के उपायों के जरिये भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाना है।
- **बजट 2020-21 से जुड़े मुख्य तथ्य**
- बजट के तीन प्रमुख घटक -
  - **महत्वाकांक्षी भारत** - भारत जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुँच और रोजगार के बेहतर अवसर हो, ताकि उनके जीवन का स्तर अच्छा हो सके।
  - **सभी के लिए आर्थिक विकास** - 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' ।
  - **जिम्मेदार समाज** - मानवीय और सहृदय, अन्त्योदय, आस्था का आधार।
- **तीन बड़े विषयों को एक साथ लाया जाना-**
  - भ्रष्टचार मुक्त, नीति निर्देशित और सक्षम शासन।
  - साफ-सुथरा और मजबूत वित्तीय क्षेत्र।
- **केन्द्रीय बजट में जीवन सुगमता को तीन प्रमुख विषयों के रूप में रेखांकित किया गया है-**
  - कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास
  - आरोग्य, जल और स्वच्छता
  - शिक्षा और कौशल
- **कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्री कार्य योजना**
- निम्नलिखित 16 सूत्री कार्य योजना के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
- कृषि, सिंचाई और संबंधित गतिविधियों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये।
- ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये।

भारतीय रेल:

- **पाँच उपाए:**
- रेल पटरियों के किनारे सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता स्थापित की जाएगी।
- 4 स्टेशनों की पुनर्विकास परियोजनाएँ और पीपीपी के माध्यम से 150 यात्री ट्रेनों का संचालन।
- आईकॉनिक पर्यटन गंतव्य को जोड़ने के लिए तेजस जैसी ट्रेनें।
- मुम्बई और अहमदाबाद के बीच हाईस्पीड ट्रेन पर सक्रियता से काम।
- 148 किलोमीटर लम्बी बेंगलुरु उप-नगरीय परिवहन परियोजना के लिए 18,600 करोड़ रुपये, मेट्रो प्रारूप के अनुसार किराया तय किया जाएगा। केन्द्र सरकार 20 प्रतिशत का लागत वहन करेगी और परियोजना लागत का 60 प्रतिशत बाहरी सहायता से उपलब्ध कराने की सुविधा देगी।
- **भारतीय रेल की उपलब्धियाः**
- 550 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा।
- कोई मानवरहित क्रॉसिंग नहीं।
- 27000 किलोमीटर की रेल लाईन का विद्युतीकरण।
- **शिक्षा एवं कौशल**
- वित्त वर्ष 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
- पुलिस संबंधी विज्ञान, फॉरेंसिक विज्ञान, साइबर-फॉरेंसिक इत्यादि के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्व विद्यालय और राष्ट्री य फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है।
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आने वाले शीर्ष 100 संस्थानों द्वारा डिग्री स्तर का पूर्णकालिक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. केंद्रीय बजट 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस बार का बजट तीन बिंदुओं एस्पिरेशनल इंडिया, सभी के लिए आर्थिक विकास, केयरिंग सोसाइटी पर केंद्रित है।
2. PM-KISAN के सभी पात्र लाभार्थी किसान क्रेटिड कार्ड योजना के अंतर्गत आएंगे।
3. 2020-21 में भारत नेट कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपये देने का प्रावधान है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of the Union Budget 2020-21:

1. This time budget focuses on three points Aspirational India, Economic Development for All, Caring Society.
2. All eligible beneficiaries of PM-KISAN will come under the Kisan Credit Card Scheme.
3. There is a provision to allocate Rs 6000 crore for the Bharat Net program in 2020-21.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3

(c) 1 and 3 (d) All of the above

नोट : 1 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 2020-21 के बजट से लोगों को सरकार से बड़ी अपेक्षाएं थीं। क्या यह बजट उनकी उम्मीदों के अनुरूप रहा? आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)

People had high expectations from the government from the 2020-21 budget. Does this budget is satisfies their aspirations? Critically evaluate. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।

Committed to Excellence